

‘चुनाव बैलेट से हुए, कांग्रेस कितनी सीटें जीती?’

● एमएलसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि चार बड़े राज्यों में एमएलसी की 28 सीटों पर चुनाव हुए और मतदान बैलेट

पेपर यानी मतपत्रों के जरिए कराया गया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं। पीएम मोदी की इस पोस्ट में चुनाव के तरीके और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया है। इन चार राज्यों के चुनाव में अलग-अलग दलों के बीच मुकाबला हुआ है। उपलब्ध नतीजों और रुझानों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी सामने आया है।

भाजपा बोली- कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि MLC चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला। ये चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराए गए थे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। उनके मुताबिक, कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाकर अपने चुनावी प्रदर्शन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।

सिंगापुर की तकनीक और यूपी का सामर्थ्य मिलकर लिखेंगे वैश्विक विकास की नई इबारत : योगी आदित्यनाथ

सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

एजेंसी लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सिंगापुर के शीर्ष उद्योगपतियों एवं निवेशकों के 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, अर्बन प्लानिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश की इच्छा व्यक्त की। यह प्रतिनिधिमंडल फरवरी में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया है।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3फीसदी बढ़कर 63फीसदी हुआ

● 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा

नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू

एजेंसी नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3फीसदी बढ़ा दिया है। बुधवार 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 60फीसदी से बढ़कर 63फीसदी हो जाएगा। इससे लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू मानी जाएगी। सरकार इसपर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले सरकार ने अप्रैल में

कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के लिए DR में 2 फीसदी का इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी के साथ DA की दर 60फीसदी पर पहुंच गई थी। अब 3 फीसदी की ताजा बढ़ोतरी के बाद यह आंकड़ा 63 फीसदी हो गया है। सरकार के इस फैसले से त्योहारों के सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और पिछले महीनों का एरियर भी खाते में आएगा।

कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा

डीए बढ़ने से सैलरी में बढ़ोतरी बेसिक पे के आधार पर तय होती है

- **मिनिमम बेसिक सैलरी वालों के लिए:** अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है, तो 3फीसदी की बढ़ोतरी के हिसाब से हर महीने 540 रुपये का इजाफा होगा।
- **हायर पे-स्केल वालों के लिए:** अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है, तो उनकी मासिक सैलरी में लगभग 1,683 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी।
- **एरियर का भुगतान:** चूंकि यह फैसला जुलाई से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया (Arrears) भी आगामी सैलरी के साथ दिया जाएगा।

चक्रवात ‘अर्नब’ने आंध्र प्रदेश में मचाई तबाही

कई मकान क्षतिग्रस्त; मुख्यमंत्री नायडू ने अमित शाह को लिखा पत्र

एजेंसी हैदराबाद। चक्रवात 'अर्नब' के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है, जबकि कई जगह पेड़ उखड़ गए, सड़कें, मकान क्षतिग्रस्त हो गए और फसलें जलमग्न हो गई हैं। रेलवे ने 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की अतिरिक्त सहायता और नुकसान का

आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राजामुद्री, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम आने जाने वाली दो दर्जन से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। भारी

बारिश, तेज हवाओं और संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के केंद्र के आसपास हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जो तेज झोंकों के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है।

भारत की बात आज पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है: राजनाथ सिंह

● आज भारत जब कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है

एजेंसी नई दिल्ली। फिलीपींस के सेबू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है। आज भारत जब कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है कि भारत क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि किसी देश की प्रतिष्ठा बढ़ने से उसके नागरिकों में भी गौरव की भावना मजबूत होती है। इसी दौरान राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिजिरो कोइजुमी के साथ भी अहम बैठक की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक जहाजों के निर्माण और वायु सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारतीय

समुदाय के साथ बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। यही सोच भारत को दूसरे देशों से अलग पहचान देती है। रक्षा मंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 12 साल पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 10वें-11वें स्थान पर था, जबकि आज वह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो भारत आर्थिक प्रगति के मामले में और आगे होता। राजनाथ सिंह ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया।

एजेंसी इफाल। मणिपुर के थौबल जिले में बुधवार को थौबल पुलिस कमांडो और 33 असम राइफल्स (एआर) की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के इकोप पाट के सामान्य क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दो एसएमजी कार्बाइन, चार डबल और सिंगल बैरल बंदूकें तथा तीन पिस्तौल बरामद की गईं। इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने चार हैंड ग्रेनेड, दो डेटोनेटर, विभिन्न प्रकार के 39 जिंदा कारतूस और कई मैगजीन भी जब्त कीं।

सरपंच उम्मीदवार

बाबू लाल जांगिड़

ग्राम पंचायत

खुरमपुरा

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

चुनाव नामांकन रैली

खुरमपुरा गाँव से गोठा स्कूल

सुबह 7:15 बजे

सभी भाई अधिक से अधिक संख्या में पधारकर हौसला बढ़ाएँ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिग्गी में टोंक व सवाईमाधोपुर के कार्यकर्ताओं से किया संवाद

‘ट्रिपल इंजन सरकार से तीन गुना होगी विकास की रफ्तार’ : सीएम पंचायत चुनावों में जीत के लिए जुटने का किया आह्वान

ग्राम विकास संकल्प पत्र से बदलेगी गांवों की तस्वीर

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले के डिग्गी में टोंक-सवाई माधोपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत समीपत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं के इसी समर्पण और जनता के आशीर्वाद से भाजपा पंचायत चुनावों में भी शानदार सफलता हासिल करेगी और गांवों में भी ट्रिपल इंजन सरकार से तीन गुना रफ्तार से विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है। ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरनेट सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र, सोलर लाइट, खेल मैदान और ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित करने का संकल्प लिया है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर 12 हजार रुपये करना, 25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, युवाओं के लिए 15 हजार नए स्कूल भवन व बड़े उद्योगों के माध्यम से रोजगार अवसर सृजित करना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले पौने तीन वर्षों में टोंक जिले में 3 हजार 841 करोड़ के कार्य करवाए जा रहे हैं। बीसलपुर परियोजना के तहत

श्री भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

गंक :- 28 अक्टूबर 2026 बुधवार

अग्रवाल सेवा सदन

खुरमपुरा

राज्यीय

भाजपा

निकाय चुनावों में जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सुविधाओं का होगा विस्तार

102 करोड़ रुपये से अधिक के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के साथ ही निवाड़ी, डिग्गी और लांबा हरिसिंह में 92 करोड़ रुपये की शहरी पेयजल योजनाओं से जुड़े कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी तरह सवाई माधोपुर जिले में 17 हजार 173 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सूरवाल से कुस्तला तक 130 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास सड़क तथा सवाई माधोपुर व रईथांकला में 400-400 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इन विकास कार्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के ध्वजवाहक और सरकार एवं जनता के बीच मजबूत सेतु हैं। 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' के संकल्प के साथ कार्यकर्ता पंचायत चुनावों में जुटें।

व्रत से परे करवा चौथ: प्रेम, परवाह और साझेदारी का पर्व



योगेश कुमार गोयल

इस पर्व की शुरुआत एक बहुत अच्छे विचार पर आधारित थी मगर समय के साथ इस पर्व का मूल विचार और परिदृश्य बदल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का फल तभी है, जब यह व्रत करने वाली महिला भूलवश भी झूठ, कपट, निंदा, अभिमान न करे। इस व्रत से जहां पति के प्रति पत्नी की निष्ठा एवं समर्पण भाव परिलक्षित होता है, वहीं यह पर्व दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास और मरोसे को मजबूत करने तथा संबंधों में मधुरता घोलने का त्यौहार है।

भारतीय संस्कृति में नारी के प्रेम और संकल्प का महापर्व करवा चौथ...

करवा चौथ पर्व का भारत की गौरवशाली संस्कृति में विशेष महत्व है क्योंकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलती हैं। भारतीय समाज में वैसे तो महिलाएं विभिन्न अवसरों पर अनेक व्रत रखती हैं लेकिन पति को परमेश्वर मानने वाली नारी के लिए इन सभी व्रतों में सबसे अहम स्थान रखता है ‘करवा चौथ’ व्रत, जो 29 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सफलता की कामना से सुहागिन महिलाओं द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला यह व्रत अन्य सभी व्रतों से कठिन माना जाता है, जो सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत एवं त्यौहार है। महिलाएं अन्न-जल ग्रहण किए बिना अपार श्रद्धा के साथ यह व्रत रखती हैं तथा रात्रि को चन्द्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। यही वजह है कि अखण्ड सुहाग का प्रतीक यह व्रत अन्य सभी व्रतों के मुकाबले काफी कठिन माना जाता है।

कहा जाता है कि इस व्रत के समान सौभाग्यदायक अन्य कोई व्रत नहीं है और सुहागिनें यह व्रत 12-16 वर्ष तक हर साल निरन्तर करती हैं, उसके बाद वे चाहें तो इसका उद्घाटन कर सकती हैं अन्यथा आजीवन भी यह व्रत कर सकती हैं। आजकल तो कुछ पुरुष भी पूरे दिन का उपवास रखकर पत्नी के इस कठिन तप में उनके सहभागी बनते हैं। दिनभर उपवास करने के बाद शाम को सुहागिनें करवा की कथा सुनती व कहती हैं तथा चन्द्रोदय के बाद चन्द्रमा को अर्घ्य देकर अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना कर प्रण करती हैं कि वे जीवन पर्यन्त अपने पति के प्रति तन, मन, वचन एवं कर्म से समर्पित रहेंगीं। पूजा-पाठ के बाद सुहागिनें अपनी सास के चरण स्पर्श कर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ पर्व के संबंध में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं लेकिन सभी कथाओं का सार पति की दीर्घायु और सौभाग्यवृद्धि से ही जुड़ा है। विभिन्न पौराणिक कथाओं के अनुसार ‘करवा चौथ’ व्रत का उद्गम उस समय हुआ था, जब देवों व दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध



में देवता परास्त होते नजर आ रहे थे। तब देवताओं ने ब्रह्माजी से इसका कोई उपाय करने की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि अगर सभी देवों की पत्नियां सच्चे एवं पवित्र हृदय से अपने पति की जीत के लिए प्रार्थना एवं उपवास करें तो देवता दैत्यों को परास्त करने में अवश्य सफल होंगे। ब्रह्मा जी की सलाह पर समस्त देव पत्नियों ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया और रात्रि के समय चन्द्रोदय से पहले ही देवता दैत्यों से युद्ध जीत गए। तब चन्द्रोदय के पश्चात् दिनभर की भूखी-प्यासी देव पत्नियों ने अपना-अपना व्रत खोला। ऐसी मान्यता है कि तभी से इसी दिन करवा चौथ का व्रत किए जाने की परम्परा शुरू हुई। करवा चौथ के व्रत के संबंध में अनेक प्रचलित कथाओं में से एक महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार धनुर्धारी अर्जुन तप करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रोपदी बहुत चिंतित हुई। उसने विचार किया कि यहाँ हर समय कोई न कोई संकट आता ही रहता है, इसलिए अर्जुन की अनुपस्थिति में इन संकटों से बचने के लिए क्या उपाय

किया जाए? तब द्रोपदी ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया और श्रीकृष्ण को अपने मन की व्यथा बताई। द्रोपदी की बात सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि पार्वती देवी ने भी एक बार भगवान शिव से बिल्कुल यही प्रश्न किया था और तब भगवान शिव ने उन्हें कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली तमाम छोटी-बड़ी बाधाओं को दूर करता है। द्रोपदी ने श्रीकृष्ण से करवा चौथ के व्रत के संबंध में विस्तार से बताने का आग्रह किया तो श्रीकृष्ण ने द्रोपदी को इस व्रत के महत्व की दर्शाती कथा सुनानी आरंभ की। भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि इन्द्रप्रस्थ नगरी में वेद नामक एक धर्मरायण ब्राह्मण के सात पुत्र व एक पुत्री थीं। विवाह के बाद जब पुत्री पहली करवा चौथ पर मायंक आई तो उसने मायंक में ही करवा चौथ का व्रत रखा लेकिन चन्द्रोदय से पूर्व ही उसे भूख सताने लगी तो अपनी लाड़ली बहन को यह वेदना भाईयों से देखी न गई। उन्होंने बहन से व्रत खोलने का आग्रह किया पर वह इसके लिए तैयार न हुई। तब भाईयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक पौपल के वृक्ष की

99वीं बार फेल काँग्रेस के शहजादे



करने के लिए कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बजाय हार के बाद सफाई देने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। चुनाव कैसे हारना है ये कला राहुल गांधी से सीखनी चाहिए। नतीजे चाहे जैसे भी आए, शहजादे का आत्मविश्वास हमेशा प्रथम श्रेणी में रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने वाले विद्यार्थी भी अपनी कमियों का विश्लेषण करते हैं, अपनी तैयारी सुधारते हैं और फिर नए उत्साह के साथ परीक्षा के मैदान में उतरते हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव में पराजय के बाद ईवीएम, निर्वाचन प्रक्रिया और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी के 99वीं बार फेल होने के बावजूद उनके नेतृत्व में सवाल ना उठकर हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी मीडिया पर तो कभी कांग्रेस के छोटे

कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया जाता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही परिवार के हाथों की कटपुतली बनकर रह गई है। राहुल गांधी को परिवारवाद की वजह से कुर्सी विरासत में मिल तो गई लेकिन उसे बनाए रखने के लिए जनता का विश्वास नहीं मिला है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसका राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि जनता का विश्वास होता है। परिवारवाद किसी व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश का अवसर दे सकती है, लेकिन जनादेश हासिल करने की गारंटी नहीं दे सकती है। राहुल गांधी को लगातार मिल रही असफलताओं से यह सिद्ध होता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीति कोई पुश्तैनी जागीर नहीं जिसमें परिवार का नाम ही योग्यता का प्रमाण-पत्र बन जाएगा।

राहुल गांधी के लिए चुनाव मानो एक ऐसा आयोजन बन गया है, जिसमें उम्मीदों की फसल हर बार लहलहाती दिखाई जाती है, मगर नतीजों की कटाई के समय कांग्रेस की राजनीतिक गोदाम खाली निकल आती है। इसके बावजूद राहुल गांधी के झूठे दावों की खेती

बंद नहीं होती है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं, हार के नतीजे आते हैं और फिर दावों की चमक फीकी पड़ जाती है। इसके बाद आरोपों की नई पटकथा तैयार कर जनादेश का अपमान और वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रामक खबरें फैलाकर अपनी नाकामी छुपाई जाती है। राहुल गांधी की हालत उस विद्यार्थी जैसी होती जा रही है, जो हर साल परीक्षा में फेल होने के बाद नई कॉपी, नया पेन और नया बैग तो खरीद लेता है, लेकिन किताब खोलने की जहमत नहीं उठता है। फिर परिणाम आने पर कहता है कि परीक्षा का माहौल ठीक नहीं था, प्रश्नपत्र कठिन था और मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई होगी। ऐसे विद्यार्थी राहुल गांधी को समझाना होगा कि जनादेश को परीक्षा में केवल परीक्षा केंद्र बदलने और झूठे आरोपों से परिणाम नहीं बदलते हैं।

मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस को अब एक नया विभाग खोल लेना चाहिए ‘चुनावी पराजय प्रबंधन विभाग’ और विभाग का आदर्श वाक्य होना चाहिए कि ःहार से घबराना नहीं है और अपना हौसला गंवाना नहीं है।ः इस विभाग का काम होगा हर हार के बाद एक नई सफाई तैयार करना, पुराने आरोपों को नए शब्दों में पेश करना और आगली बार जीत की नई भविष्यवाणी कर जनता को गुमराह करना। इस विभाग में अनुभव की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि विगत कई वर्षों से चुनावी हारों के नतीजों के बाद सफाई देने का पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव जमा हो चुका है। कांग्रेस के 56 वर्षीय युवा शहजादे राहुल गांधी को चुनावी हार का शतक पूरा करने हेतु अग्रिम शुभकानाएं देता हूँ।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

स्रोत हो सुरक्षित

पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मों का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन-विरोधी कार्यों में लिस लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट’ यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक मुद्दे में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मों के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच-पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लागू करने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।

इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच-पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोटिंग में बाधा न बनेगा।

चिंतन-मनन

सुखी रहना है तो ईश्वर से शिकायत न करें

इंसानों की एक सामान्य आदत है कि तकलीफ में वह भगवान को याद करता है और शिकायत भी करता है कि यह दिन उसे क्यों देखने पड़ रहे हैं। अपने बुरे दिन के लिए इंसान सबसे ज्यादा भगवान को कोसता है। जब भगवान को कोसने के बाद भी समस्या से जल्दी राहत नहीं मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसका कारण यह है कि उसे लगता है कि जो उसकी मदद कर सकता है वही कान में रूई डालकर बैठ है। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि दुख के समय भगवान को कोसने की बजाय उसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे और समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ढूंढ लेंगे। भगवान किसी को परेशानी में नहीं डालते और न ही वह किसी को परेशानी से निकाल सकते हैं। भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। भगवान सिर्फ एक जरिया हैं जो रास्ता दिखाते हैं चलना किधर है यह व्यक्ति को खुद ही तय करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को खुद स्पष्ट किया है।

कांग्रेस के 56 वर्षीय युवा शहजादे राहुल गांधी चुनावी हार का शतक पूरा करने की दहलीज पर खड़े हैं। वो ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले यशस्वी एवं सफल नेता होंगे, जिनके नेतृत्व में चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है, अब वे जल्द ही चुनावी मैदान में हार का शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उनके इस ताबड़तोड़ चुनावी हारों के प्रदर्शन से रोहित शर्मा के दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी खतरे में है। हालांकि रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मैदान में दोहरा शतक लगाकर देश का गौरव बढ़ाया था। वहीं राहुल गांधी चुनावी हार का शतक लगाकर गांधी परिवार का गौरव बढ़ाएंगे। न भूतो न भविष्यति- जो पहले कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में कभी होगा ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले राहुल गांधी देश व दुनिया के एकमात्र नेता होंगे। वैसे भी महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। उनके इस सपने को साकार

त्योहारों के बीच सियासी टकराव: व्यापारी क्यों बन रहे हैं आंदोलन के मोहरे?



सौरभ वार्धन्य

देश में त्योहारों का मौसम बाजारों में रौनक, कारोबार में तेजी और आम लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आता है। दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान व्यापारी वर्ग पूरे साल की कमाई के एक बड़े हिस्से की उम्मीद करता है। दुकानदारों से लेकर छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और कर्मचारियों तक, लाखों लोगों की आजीविका इन दिनों के कारोबार पर निर्भर रहती है। ऐसे समय में यदि राजनीतिक आंदोलन, चुनावी रैलियां और विरोध-प्रदर्शन बाजारों तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने लगें, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि अखिर इस टकराव की कीमत व्यापारी वर्ग ही क्यों चुकाए? एक नवंबर को प्रस्तावित चुनावी रैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक विरोध के बीच व्यापारिक संगठनों की ओर से त्योहारों के मद्देनजर उड़ाई जा रही मांगों ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को नई दिशा दे दी है। एक तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की जवाबदेही का सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग चाहता है कि त्योहारों के समय उसका कारोबार बाधित न हो। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन की रणनीति तय करते समय आम नागरिकों और व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। सरकार से सवाल पूछना, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना और संवैधानिक संस्थाओं की

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। यदि विपक्ष को चुनाव आयोग के कामकाज पर आपत्ति है, तो उसे तथ्य, दस्तावेज और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने या राजनीतिक संदेश देने से नहीं मापी जानी चाहिए। यह भी देखना आवश्यक है कि उस आंदोलन का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। त्योहारों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही, माल की आपूर्ति, यातायात और दुकानों के संचालन में व्यवधान छोटे व्यापारियों के लिए गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

बड़े कारोबारी कुछ समय का नुकसान सहन कर सकते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार, दैनिक आय पर निर्भर विक्रेता और सीमित पूंजी से कारोबार करने वाले व्यापारी हर दिन की कमाई पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में व्यापारिक संगठनों की मांग को केवल राजनीतिक विरोध के चरम से देखना उचित नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक है। यदि आंदोलन को लेकर राजनीतिक गतिरोध बढ़ रहा है, तो सरकार और संबंधित संस्थाओं को संवाद का रास्ता तलाशना चाहिए। हालांकि, यह निकर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हैं कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा राजनीतिक पेच खड़ा किया है, जिससे आंदोलन समाप्त हो जाए या विपक्ष दबाव में आ जाए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी आरोप की विश्वसनीयता तथ्यों से तय होती है। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की शिकायतों का जवाब दे, चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि के कारण आम नागरिकों के अधिकारों तथा आजीविका पर अनावश्यक असर न पड़े।

इसी तरह विपक्ष को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका आंदोलन किन ठोस मांगों पर आधारित है, उसकी समय-सीमा क्या है और आम लोगों को कम से कम परेशानी पहुंचाते हुए उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी मांग पूरी होने पर आंदोलन समाप्त हो सकता है, राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण विषय है। यदि विपक्ष का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, तो उसे अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग को भी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पदाधिकारी का इस्तीफा मांगना और उसे तत्काल स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख का पद किसी राजनीतिक दल की इच्छा से संचालित नहीं हो सकता। उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया कानून तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए यह कहना कि केवल इस्तीफा होते ही तीस सेकंड में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक वक्तव्य तो हो सकता है, लेकिन इसे समस्या के समाधान की गारंटी नहीं माना जा सकता। यदि वास्तविक उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बहाल करना है, तो समाधान पारदर्शी जांच, तथ्यों के सार्वजनिक स्पष्टीकरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन में तलाशना होगा। केवल इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना या बिना जवाब दिए मांग को खारिज कर देना, दोनों ही स्थितियां राजनीतिक गतिविध को बढ़ा सकती हैं। व्यापारी किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। बाजारों में काम करने वाले लाखों लोगों के सामने किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, माल की खरीद और बैंक की किस्तों जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। त्योहारों के समय बिज्री प्रभावित होने का नुकसान केवल दुकान के मालिक को नहीं, बल्कि इससे जुड़े पूरे परिवार और कर्मचारियों को भी उठाना पड़ता है।इसलिए व्यापारिक संगठनों की मांगों को गंभीरता से सुनना सरकार और विपक्ष, दोनों की ज़िम्मेदारी है। यदि रैली या आंदोलन के लिए स्थान, समय और मांग में बदलाव करके व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ऐसा करने में किसी पक्ष को राजनीतिक हार नहीं माननी चाहिए।सरकार को कानून-व्यवस्था और नागरिक



सुविधाओं का संतुलन बनाए रखना चाहिए। विपक्ष को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार इस्तेमाल करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी रणनीति से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। प्रशासन को भी निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए यातायात, सुरक्षा और बाजारों के संचालन के लिए स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल व्यापारियों को अपने पक्ष में खड़ा करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करें। व्यापारिक संगठनों को भी अपनी मांगें स्पष्ट रूप से सामने रखनी चाहिए और राजनीतिक विवादों में किसी एक पक्ष का औज़ार बनने से बचना चाहिए। एक नवंबर की रैली और आंदोलन को लेकर यदि कोई विवाद है, तो संबंधित पक्षों के बीच तत्काल बातचीत होनी चाहिए। रैली के समय और स्थान का ऐसा निर्धारण किया जा सकता है, जिससे विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहे और त्योहारों का कारोबार भी प्रभावित न हो। इसके साथ ही चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक संवाद होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी विपक्ष का जिम्मेदार अचरन भी है। विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता के हितों की रक्षा करना उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। इसी प्रकार सरकार को भी आलोचना को दबाने के बजाय उसका उत्तर देना चाहिए। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि राजनीतिक संघर्ष के बीच भी जनता के हित सर्वोपरि रहें।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

दिल्ली दंगा 2020 : मोहसिन हत्याकांड में 5 दोषियों की 7 साल की कैद बरकरार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोहसिन की हत्या के मामले में पांच दोषियों की सजा को बरकरार रखकर उनकी अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने अमन कश्यप, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, आशीष और अरुण कुमार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा को सही ठहराया। निचली अदालत ने इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 148 (घातक हथियारों से दंगा करना) के तहत दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को महत्वपूर्ण माना, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता हथियारों से लैस भीड़ में सबसे आगे थे और उन्होंने अन्य लोगों को मोहसिन पर हमला करने के लिए उकसाया था। दोषियों ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए और स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। हालांकि, अदालत ने दलीलों को खारिज किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर वे बरी होने का दावा नहीं कर सकते कि भीड़ के किस सदस्य ने पीड़ित के सिर पर जानलेवा चोट पहुंचाई थी। अदालत ने कहा कि साक्ष्य केवल भीड़ में अपीलकर्ताओं की मौजूदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से दूसरों को उकसा रहे थे। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग इलाके में मोहसिन पर हमला करने वाली दंगाई भीड़ का साझा गैरकानूनी उद्देश्य उसे शारीरिक चोट पहुंचाना था, जिससे उसकी मौत हुई। निचली अदालत ने भी अपने फैसले में इन तथ्यों को साबित पाया था।

अंग्रेजी कमजोर होने पर वेंटर को थप्पड़, ताज होटल ने ग्राहक पर लिया कड़ा एक्शन

आगरा। आगरा के ताज होटल में घटना सामने आई है, जहाँ एक ग्राहक ने कथित तौर पर वेंटर काफ़ी को सिर्फ़ इसलिये थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल सका था। होटल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने घटना और होटल द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण साझा किया। यह मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। होटल कर्मचारी के मुताबिक, वेंटर काफ़ी होटल के रेस्टोरेंट में एक ग्राहक को खाना सर्व कर रहे थे। बातचीत के दौरान अंग्रेज़ी को लेकर कुछ गलतफहमी हुई। काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते थे, और इसी बात पर ग्राहक ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। होटल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए यह घटना बेहद हैरान करने वाली थी, क्योंकि काफ़ी केवल अपना काम कर रहे थे और एक छोटी सी गलतफहमी के बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ग्राहक को होटल कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने या हाथ उठाने का अधिकार नहीं है।

लखनऊ ट्रिपल मर्डर : गोल्ड मेडलिस्ट शूटर का बेखौफ अंदाज

लखनऊ। लखनऊ में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का आरोपी ऋषभ शुक्ला, वारदात के बाद भी अपनी बेखौफ हरकतों से सभी को हैरान कर गया। तीन लोगों की हत्या करने के बाद वह एक हाथ में पिस्टल और दूसरे में मैगजिन लिए घर के बाहर ही बैठा रहा, घायलों की मदद के लिए आने वालों को भी गोली मारने की धमकी दी, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पुलिस अधिकारी और आम लोग, हर कोई इस बात से स्तब्ध था कि एक अकेला व्यक्ति कैसे तीन लोगों की जान ले सकता है। इसके पीछे उसकी विशेष ट्रेनिंग और शूटिंग का अनुभव प्रमुख वजह है। ऋषभ एक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर हैं और हथियार चलाने की विशेष ट्रेनिंग मिली हुई थी। गोली चलाने के उसके सधे हुए अंदाज और अचूक निशाने ने सभी को हैरान कर दिया।

आज का बांग्लादेश झूठे मुकदमों और मानवाधिकारों के उल्लंघन वाला देश बन गया -शेख हसीना ने रहमान सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के दमन का लगाया आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि देश में «बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, तलाशी अभियान और लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पीएम तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक विरोधियों का दमन करने का भी आरोप लगाया। शेख हसीना ने बांग्लादेश अवामी लीग द्वारा सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि आज का बांग्लादेश झूठे मुकदमों और मानवाधिकारों के उल्लंघन वाला देश बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में न तो कानून का राज है, न लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं और न ही आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ‘‘देश के कई इलाकों में सामूहिक छापेमारी और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं।



जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि धांधली से हुए चुनाव के जरिए सत्ता में आई सरकार ने स्पष्ट रूप से देश से अवामी लीग का सफाया करने का अभियान शुरू कर दिया है। बीएनपी सरकार के आर्थिक प्रबंधन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गैस, बिजली, ईंधन और उर्वरकों की कमी है। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की कीमतें और बेरोजगारी बढ़ रही है,

मीलें और कारखाने बंद हो रहे हैं और निवेश की गति धीमी हो गई है। बता दें बांग्लादेश में छत्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त, 2024 को शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद वह देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह यहीं रह रही हैं।

अखिलेश का आरोप.... भाजपा वोट से नहीं, बल्कि खोट से चुनाव जीत रही

लखनऊ , एजेंसी। उत्तरप्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव परिणामों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट से नहीं, बल्कि खोट से चुनाव जीत रही है, और मतगणना में धांधली व साजिश करके सपा प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया। सपा प्रमुख अखिलेश ने विशेष रूप से गोरखपुर में सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी की हार को मतगणना में धांधली और साजिश का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपाइयों और सॉलिस अधिका‍रियों ने एमएलसी चुनाव जीतने की सभी हद्दें पार कर दीं। डॉ. त्रिपाठी की हार का कारण केवल उनका सपा उम्मीदवार होना नहीं, बल्कि हाता नहीं



भाता की सोच है। अखिलेश ने दावा किया कि शिक्षकों से चारा इकट्ठा कराया गया और शिक्षक समाज डॉ. त्रिपाठी के उत्पीड़न और उनके आंसुओं को कभी नहीं भूलेगा।

आधिकारिक परिणामों के अनुसार, भाजपा ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी दो महत्वपूर्ण सीटों पर सफलता हासिल की है। वागणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

से सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय शिक्षक समाज और अखिलेश यादव की सकारात्मक सोच को दिया। यादव ने स्पष्ट किया कि इस चुनाव पर यूजीसी बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा चाहने वाले शिक्षक मजबूती से सपा के साथ खड़े रहे। इसी क्रम में, आगरा खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर भी सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने द्वितीय वरीयता के मतों के बाद 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की। आगरा में मतगणना के दौरान हुए हंगामे और मारपीट पर डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी पर विवाद शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्टिंग रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

राकांपा ने मुंबई की कमान जीशान सिद्दीकी को सौंपी, उमेश पाटिल बने राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्वादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने अपनी मुंबई इकाई का अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य जीशान सिद्दीकी को नियुक्त किया है, जबकि उमेश पाटिल को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। यह घोषणा राकांपा प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने की। दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ नेता पार्थ पवार का आभार व्यक्त किया। सिद्दीकी ने कहा कि उनका लक्ष्य मुंबई में पार्टी का विस्तार करना और सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाना है। उन्होंने दिवंगत अजित पवार और अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सुनेत्रा ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने आधिकारिक आवास देवगिरि में आयोजित समारोह में दोनों नेताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर पार्टी के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। सुनेत्रा पवार ने विश्वास जताया कि पाटिल और सिद्दीकी दिवंगत अजित पवार के आदर्शों, दृष्टिकोण और जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। जीशान अक्टूबर 2024 में अपने पिता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद राकांपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें बांद्रा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरुण सरदेसाई से हार गए थे। बाद में, वे मई 2026 में विधान परिषद सदस्य बने।



सीएपीएफ जवानों में बढ़ता मानसिक तनाव: सात साल में 1,016 आत्महत्याएं और 24 फैंट्रिसाइड

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में जवानों पर अत्यधिक काम का दबाव और गहरा मानसिक तनाव गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2025 के बीच इन बलों के 1,016 जवानों ने आत्महत्या की है, जबकि बीते पांच वर्षों में अपने ही साथियों पर गोली चलाने यानी फैंट्रिसाइड की 24 गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में 29 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हेड कंस्टेबल अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने चार साथियों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की घटना ने गंभीर समस्या को फिर से उजागर किया है। यह घटना बच्चे को लाने के मुद्दे पर हुए विवाद के बाद हुई थी, जिसके बाद अवधेश ने अपनी एके-47 राइफल से गोलीबारी कर दी थी। विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि जवानों में बढ़ते तनाव और इस दुखद परिणामों के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सीएपीएफ और असम राइफल में 93,139 खाली पद मौजूदा जवानों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जिससे उनकी इश्टी का समय बढ़ जाता है और उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता। रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण के अनुसार, कई जवानों को दिनभर में मुश्किल से पांच घंटे की नींद नसीब होती है, जो उनके शारीरिक और मानसिक

स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। छुट्टी का प्रावधान होने के बावजूद, जवानों की शिकायत है कि जरूरत के समय छुट्टी मिलना बेहद मुश्किल होता है। सीआरपीएफ जवान विनीत सिंह की पत्नी नेहा सिंह का मामला इसका एक दुखद उदाहरण है, जहां विनीत को छुट्टी न मिलने और अत्यधिक तनाव के बीच उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा, पदेन्नति में देरी भी जवानों में गहरा असंतोष बढ़ाती है। कई कर्मियों को अगली रैंक तक पहुंचने के लिए 18 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है, और 2021 के बाद से कैडर रिव्यू न होने के कारण लगभग 13 हजार अधिकारी पदेन्नति की राह देख रहे हैं। परिवार से दूरी भी एक बड़ा कारक है। जवानों की तेनाती अक्सर सीमावर्ती, पहाड़ी, जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में होती है, इसतरह के स्थानों पर परिवार को साथ रखना संभव नहीं हो पाता। शहरों में भी पर्याप्त सरकारी आवास नहीं होने से कई जवानों को परिवार से दूर रहना पड़ता है। हालांकि ई-आवास पोर्टल के जरिए 1.46 लाख से अधिक पारिवारिक आवास आवंटित किए गए हैं, फिर भी यह सुविधा सभी कर्मियों को उपलब्ध नहीं हो पाती। अधिकारियों और जवानों के बीच संवाद की कमी, कथित भेदभाव और दुर्व्यवहार भी जवानों के तनाव को बढ़ाते हैं। कई जवानों को अक्सर यह डर रहता है कि शिकायत करने से उनकी



इश्टी, पोस्टिंग या करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, खाली पदों को भरना, इश्टी और आराम का संतुलन बनाना, समय पर छुट्टी और पदेन्नति सुनिश्चित करना, तथा एक भयमुक्त शिकायत प्रणाली विकसित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि जवानों को मानसिक सुरक्षा मिल सके और ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

जलकूटनीति: भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश को दो टूक... पानी के बदले शांति देना होगा जियोस्ट्रैटजिस्ट ने दिया इजरायल-जॉर्डन मॉडल का उदाहरण

नई दिल्ली , एजेंसी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जल-साझाकरण समझौतों को लेकर बड़ा रणनीतिक बदलाव लाने का संकेत दिया है। अब वह पानी को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा स्थापित करने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देख रहा है। जियोस्ट्रैटजिस्ट ब्रह्मा चेलानी ने इस बारे में इजरायल और जॉर्डन के बीच अपनाए गए मॉडल को भारत के लिए अपनाने का सुझाव दिया है, जहां जल-बंटवारा व्यापक शांति समझौते का अभिन्न अंग है। जियोस्ट्रैटजिस्ट चेलानी का मानना है कि भारत को नदियों के ऊपरी हिस्से में स्थित होने का लाभ उठाना चाहिए और पानी को शांति व सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उनका सुझाव है कि इजरायल-जॉर्डन मॉडल एक उपयोगी टेम्पलेट

पेश करता है, क्योंकि यह जल बंटवारे को एक बड़े शांति और सुरक्षा ढांचे से जोड़ता है। इस मॉडल के तहत, इजरायल और जॉर्डन के बीच 1994 की शांति संधि का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों देश जल बंटवारे के लिए पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। जॉर्डन जानता है कि यदि वह शांति शर्तों का उल्लंघन करता है, तब इजरायल उसके लिए जल संबंधी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। वहीं, इजरायल भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जॉर्डन के साथ सहयोग बनाए रखने को महत्वपूर्ण मानता है। कुल मिलाकर, जल बंटवारे को शांति प्रक्रिया के भीतर ही संस्थागत रूप दिया गया है। भारत की रणनीतिक परिस्थितियां इजरायल से भिन्न हैं, इसलिए इस मॉडल को सीधे नकल करने के बजाय क्षेत्रीय भौगोलिक और रणनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव की

आवश्यकता होगी। भारत का मानना है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि अनिश्चितकाल के लिए की थी, लेकिन पड़ोसी देश ने इसके बावजूद 1960 की संधि के पांच साल बाद ही भारत पर हमला किया और तब से आतंकवाद व छत्र युद्ध का सिलसिला कभी रुका नहीं। इस तरह, बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रही है। इस समझौते के समय से अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, और वहां भी कश्त्रपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है जो भारत-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत के लिए ऐसी परिस्थितियों में गंगा जल संधि को यूं ही आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 के आतंकी हमले के बाद पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकता की नीति अपनाकर सिंधु



जल समझौते पर एक तरह से रोक लगा दी है। भारत अपने संप्रभु फैसले और बुलंद हौसले से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जियोस्ट्रैटजिस्ट चेलानी के अनुसार, यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते हैं कि भारत निचले बहाव वाले देश के साथ नदी जल को

लंबे समय तक साझा करने पर सहमत हो जाए, तब उन्हें शांति के लिए जल की पदों व्यवस्थाओं के तहत शांति बनाए रखने के इस्तरह के ठोस वादे स्वीकार करने होंग, जिन्हें अमल में लाना आसान हो।

झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र : संशोधित खनन कानून और एसआईआर पर चर्चा

रांची, एजेंसी। झारखंड सरकार ने संशोधित खनन कानून और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर व्यापक चर्चा के लिए 25 नवंबर से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अपर मुख्य सचिव, वंदना दादेल ने पुष्टि कर बताया कि सत्र 25 और 26 नवंबर को चलेगा। राज्य का सत्तारूढ़ गठबंधन केंद्र द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम तथा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का लगातार विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री सोरेन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि एमएमडीआर अधिनियम और एसआईआर को लेकर उत्पन्न मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा जरूरी है, इसलिए संक्षिप्त सत्र बुलाया गया है।

नांगल राजावतान: वार्ड नंबर 6 से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी रवि शंकर महावर ने किया तूफानी जनसंपर्क, मांगा जनता का आशीर्वाद

सामुदायिक प्रेषण

नांगल राजावतान/रोशन लाल मीणा। पंचायत समिति चुनावों की सरगमियों के बीच वार्ड नंबर 6 से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी रवि शंकर महावर ने अपने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी ने वार्ड के विभिन्न गांवों एवं ढाणियों में घर-घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।जनसंपर्क के दौरान रवि शंकर महावर का ग्रामीणों ने माला पहनाकर और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।

विकास और पारदर्शिता रहेगी पहली प्राथमिकता

मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशी रवि शंकर महावर ने कहा, ‘वार्ड नंबर 6 का सर्वांगीण विकास ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं जैसे- पक्की सड़कों का निर्माण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और युवाओं के लिए बेहतर अवसरों को धरातल पर उतारना मेरी पहली



प्राथमिकता रहेगी।' उन्होंने आगे कहा कि पंचायत समिति में वार्ड की हर समस्या को मजबूती से उठवाया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।

ग्रामीणों का मिला अपार समर्थन

जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय निवासियों और बुजुर्गों ने प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देते हुए अपना पूर्ण समर्थन देने का भरपौरा जताया। जनसंपर्क कार्यक्रम में क्षेत्र के कई स्थानीय गणमान्य नागरिक, युवा और बड़ी संख्या में समर्थक साथ रहे।

नाहरगढ़ किले की सड़क दुरुस्त करें, दुर्घटना हुई तो सरकार-प्रशासन जिम्मेदार होगा: रवि शंकर धाभाई संयोजक- लाइसेंस टुरिस्ट गाइड समिति

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, लाइसेंस पर्यटक गाइड एवं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के टुरिस्ट फैसिलिटेटर रवि शंकर धाभाई ने राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाहरगढ़ किले की जर्जर सड़क का तत्काल पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण करवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अक्टूबर से फरवरी तक पर्यटन सीजन में देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के बावजूद सड़क की बदहाल स्थिति गंभीर दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। रवि शंकर धाभाई ने मुख्यमंत्री से सड़क के गहरे भरवाने, खतरनाक मोड़ों पर क्रैश बैरियर लगाने, झाड़ियों की कटाई तथा नाहरगढ़-जयराढ़ मार्ग पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात करने की मांग की है। उन्होंने पर्यटक गाइड प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा पूर्व में भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई की जांच कराने का भी आग्रह किया। रविशंकर धाभाई ने



स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पत्र पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई और नाहरगढ़ घाटी में कोई दुर्घटना या जनहानि होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं संबंधित प्रशासन की होगी।

पंचायत आम चुनाव-2026 :छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर को होगी मतदान 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतपत्र के माध्यम से होगा

प्रातः 8 से 11 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे नाम निर्देशन पत्र, दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जिले में द्वितीय चरण में छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1,223 वार्डों में पंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया गुरुवार, 29 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। मतदान 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से

सायं 6 बजे तक मतपत्र के माध्यम से होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने बताया कि द्वितीय चरण में बैजूपाड़ा, बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर एवं मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति क्षेत्रों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की स्वीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगी। इसके बाद अभ्यर्थी अपराह्न 2 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित

की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर को छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1,223 वार्डों में पंच पदों के लिए मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतपत्रों के माध्यम से कराया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैजूपाड़ा पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों एवं 148 वार्डों, बांदीकुई की 44 ग्राम पंचायतों एवं 380 वार्डों, बसवा की 18 ग्राम पंचायतों एवं 166 वार्डों, महवा की 23 ग्राम पंचायतों एवं 201 वार्डों, मंडावर की 15 ग्राम पंचायतों एवं 133 वार्डों तथा मनोहरपुर खेड़ला की 23 ग्राम पंचायतों एवं 195 वार्डों में सरपंच-पंच के लिए चुनाव होगा।

पंचायत आम चुनाव-2026 :दौसा जिले में द्वितीय चरण में सायं 6 बजे तक 67.38 प्रतिशत मतदान जिला परिषद के 13 एवं पंचायत समिति के 98 वार्डों के लिए हुआ मतदान

बुजुर्गों, दिव्यांगों और नवमतदाताओं में दिखा उत्साह, आदर्श मतदान केंद्र रहे आकर्षण का केंद्र

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के अंतर्गत दौसा जिले में द्वितीय चरण में बुधवार को छह पंचायत समिति क्षेत्रों बैजूपाड़ा, बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर एवं मनोहरपुर खेड़ला में मतदान संपन्न हुआ। इन क्षेत्रों में जिला परिषद के 13 एवं पंचायत समिति के 98 वार्डों के लिए सायं 6 बजे तक 67.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। बुजुर्गों, दिव्यांगों और पहली बार मतदान करने वाले नवमतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

मंडावर पंचायत समिति में सर्वाधिक 68.61 प्रतिशत मतदान

सायं 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंडावर पंचायत समिति में

सर्वाधिक 68.61 प्रतिशत मतदान हुआ। मनोहरपुर खेड़ला में 68.14 प्रतिशत, बसवा में 68.31 प्रतिशत, महवा में 67.55 प्रतिशत, बैजूपाड़ा में 67.36 प्रतिशत तथा बांदीकुई पंचायत समिति में 66.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान सुबह से ही मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। सुबह 10 बजे तक विभिन्न पंचायत समितियों में 14.77 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा 34.53 प्रतिशत तथा दोपहर 3 बजे तक 50.51 प्रतिशत के बीच पहुंच गया। इसके बाद भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का क्रम जारी रहा और शाम 6 बजे तक 67.38 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं

मतदान के दौरान बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला प्रशासन की ओर से इन मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं, ताकि उन्हें

आदर्श मतदान केंद्र बने आकर्षण का केंद्र

मतदान के दौरान कई स्थानों पर आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए। इन केंद्रों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया, जिससे वे मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। मतदान केंद्रों पर बेहतर वातावरण और सुविधाओं ने मतदान के अनुभव को खास बनाया।

मतदान के साथ सेल्फी का भी रहा क्रेज

लोकतंत्र के उत्सव में मतदान के साथ सेल्फी लेने का उत्साह भी देखने को मिला। युवा हों या बुजुर्ग, विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं ने मतदान के बाद सेल्फी लेकर इस खास पल को यादगार बनाया। नवमतदाताओं सहित कई मतदाता समूह में मतदान केंद्र पहुंचे और अपने पहले वोट तथा मतदान के अनुभव को यादगार बनाया।

पहली बार वोट डालने पहुंचे नवमतदाता

पंचायत चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई नवमतदाता अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने जीवन के पहले वोट का प्रयोग किया। कई स्थानों पर युवा समूह में मतदान करने पहुंचे। पहली बार मतदान करने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह रहा। नवमतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाई।

मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने में परेशानी नहीं हो। मतदान केंद्रों तक आने-जाने के लिए वाहनों, व्हीलचेयर तथा वॉलंटियर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनएसएस-एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य वॉलंटियर्स ने

बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और मतदान प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। इन व्यवस्थाओं से मतदाताओं को सहज एवं सुविधाजनक तरीके से मतदान करने में मदद मिली।



और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री ममता भूपेश, दौसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओढ़, दौसा विधायक डी.सी. बैरवा, कांग्रेस नेता अशोक डगोलाई, गुल किशोर आलुदा, सतपाल, मुकेश ठीकरिया, ऋषभ शर्मा और मण्डल अध्यक्ष विवेक शर्मा।

इनके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्र की आम जनता उपस्थित रही।

नेताओं ने की कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील

सभा को संबोधित करते हुए दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार जयंत मीणा को भारी मतों से विजय बनाएं। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने अपने संबोधन में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा



सामुदायिक प्रेषण

नांगल राजावतान/रोशन लाल मीणा। नांगल राजावतान ब्लॉक में पंचायती राज चुनावों की सरगमियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दौसा विधायक डी.सी. बैरवा ने नांगल राजावतान ब्लॉक का दौरा कर कांग्रेस जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया तथा चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक डी.सी. बैरवा ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचकर आमजन से मुलाकात की तथा क्षेत्र के चहुमुखी विकास और जनहितैषी नीतियों के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की।



इन प्रत्याशियों के समर्थन में मांगा समर्थन:

जनसंपर्क के दौरान विधायक ने जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार प्रमोद मीणा व रजनी मीणा, तथा पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार रजनी बैरवा, गिराज रिंग्या, रामखिलाड़ी मीणा और रुग्ना मीणा के समर्थन में वोट मांगे और ग्रामीणों से कांग्रेस पार्टी के ह्दय के निशान पर बटन दबाने का आह्वान किया।

वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद:

इस दौरान विधायक के साथ ऋषभ शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य मुकेश ठीकरिया, लाखाराम, अर्जुन मीणा, देवीसहाय, रामकिशन अभयपुरा, पूर्व प्रधान दिनेश कुमार एवं जगदीश मीणा नांगल राजावतान कांग्रेस उम्मीदवार रवि शंकर महावर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पंचायती राज आम चुनाव-2026 :फर्जी दस्तावेजों पर अंकुश लगाने के लिए ई-मित्र केंद्रों के निरीक्षण का अभियान जारी

दौसा ब्लॉक में तीन दिन में 38 ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर कार्रवाई

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के मद्देनजर फर्जी मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का अभियान तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा के निर्देश पर



दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में संयुक्त टीमों ने तीन दिन में कुल 38 ई-मित्र

केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उप जिला कलक्टर संजू मीना ने बताया कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं प्रोग्रामर की संयुक्त टीमों ने ई-मित्र केंद्रों पर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, निर्धारित दरों की पालना तथा दस्तावेजों से संबंधित अनियमितताओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान 8 ई-मित्र केंद्रों पर निर्धारित दरों की सूची प्रदर्शित नहीं मिली, जबकि 2 केंद्रों पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की अनियमितता सामने आई। संबंधित संचालकों पर विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शास्ति आरोपित करते हुए उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिए

पाबंद किया गया। उन्होंने सभी ई-मित्र संचालकों को निर्देश दिए कि मतदाताओं के मूल दस्तावेजों में किसी प्रकार की काट-छांट या छेड़छाड़ नहीं करें तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसी गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित ई-मित्र केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी ई-मित्र संचालकों को सरकारी सेवाएं पारदर्शिता के साथ निर्धारित दरों पर तथा विभागीय नियमों के अनुरूप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, चुनाव के दौरान दस्तावेजों से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लेने की बात कही।

सोमपुर में स्वीप टीम की बाल विद्यार्थी रैली, वोट चौपाल से दिया मतदान का संदेश

सामुदायिक प्रेषण

रामसिंह रावत /रघुनाथपुरा /बड़ीसादड़ी । बड़ीसादड़ी उपखंड क्षेत्र में स्वीप टीम लगातार नित नए प्रयोगों से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में आज सोमपुर में बाल विद्यार्थियों की रैली और वोट चौपाल का आयोजन किया गया। संवाद के माध्यम से अभिभावकों को मतदान का संदेश दिया गया। ढोल-नारों के साथ निकली रैली। नारे अब गाँव-गाँव, गली-मोहल्ले में रोज गूँज रहे हैं। 114 और 16 नवंबर को मतदान का आह्वान स्वीप टीम प्रभारी भगवत सिंह शक्तावत ने बताया कि अब तक उपखंड की शत प्रतिशत ग्राम पंचायत मुख्यालयों सहित दर्जनों विद्यालयों में विद्यार्थियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है इसके अलावा चौपाल, रैलियां, रंगोली, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, तिरंगा यात्रा, नव मतदाता अभिनंदन, गरबा महोत्सव, नवरात्रि ज्वार विसर्जन, युथ चला बुथ की ओर जैसे कार्यक्रमों से 160 राजस्व गांवों में स्वीप का संदेश पहुंचाया गया



है उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2026 को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा 16 नवंबर 2026 को पंच-सरपंच चुनाव में सभी मतदाता अपना मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र रूपी महापर्व को सफल बनाएं।

भगवत सिंह शक्तावत ने कहा कि आपणों वोट लोकतंत्र रो प्राण है, इसका जरूर दान करो। सुनो रे भाईदा वोट जरूर दिजो। वोट अपनों अधिकार है, वोट देना अपनों धर्म है। उन्होंने 18 वर्ष के नवयुवकों से नाम जुड़वाने और प्रवासी मतदाताओं को मतदान के दिन बुलाने की अपील की। साथ ही मत चुके मतदान का नारा दिया

शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ढोल की थाप पर नारे लगाए:

- वोट हमारी जिम्मेदारी
- बाई-बापू ने केनो है, वोट सबने देना है
- स्वीप टीम रो केणो है, वोट सबने देणो है
- ना नोट से ना दारू से, वोट देना आत्मा की आवाज से

अभियान का नेतृत्व

यह अभियान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजु एवं जिला स्वीप प्रभारी विनय पाठक के निर्देशन में रितमि अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा के नेतृत्व में चल रहा है। टीम में स्वीप प्रभारी लक्ष्मण लाल मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश थाकड़, खेमराज मीणा, कैलाश सिंह रावत, शंभू कीर, रामेश्वर मेघवाल, हुसेन अली और मीडिया संकलन के लिए सतपाल धाकड़ सहयोग कर रहे हैं।

दौसा जिला परिषद वार्ड 14 के चुनाव कार्यालय का सांसद मुरारी लाल मीणा ने किया उद्घाटन

पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज

सामुदायिक प्रेषण

नांगल राजावतान/रोशन लाल मीणा। जिला परिषद वार्ड नंबर 14 के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगमियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा ने वार्ड 14 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जयंत मीणा के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद आयोजित एक विशाल चुनावी सभा को मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस अवसर पर क्षेत्र



के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सभा के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी की नीतियों और स्थानीय विकास के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। समारोह में दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी कार्यालय उद्घाटन और चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 80 फीट सेक्टर रोड को कराया अतिक्रमण मुक्त



सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा बुधवार को जोन-सी-1 के क्षेत्र में अतिक्रमणों पर सामूहिक अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान मालवीय नगर की नंदपुरी कॉलोनी से जगतपुरा तक 80 फीट सेक्टर रोड को सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को ध्वस्त कर हटाया गया। जेडीएफ के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनंद शर्मा ने बताया कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम एवं द्वितीय के पर्यवेक्षण में संचालित अभियान के दौरान सड़क सीमा में बने अवैध मकानों, दुकानों, बाउंड्रीवाल, चबूतरों एवं अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई उप नियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय एवं चतुर्थ तथा जोन-सी, बी, 09 एवं 12 के प्रवर्तन अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। जयपुर पुलिस आवृत्तालय से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल, स्थानीय जवाहर संकलन थाना पुलिस, जोन के राजस्व एवं तकनीकी स्टफ के सहयोग से प्रवर्तन दस्ते ने लोडक्रेन, जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण हटाए। अभियान के बाद संबंधित 80 फीट सेक्टर रोड को